PK टाइम्स

दैनिक
लोक टुडे
जनता की आवाज...
विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 13 | अंक: 34 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | गुरुवार 20 अगस्त 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

कोलकाता अग्निकांड: होटल में भीषण आग से 9 की मौत

एजेंसी। कोलकाता

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुधवार सुबह एक भयावह अग्निकांड ने शहर को झकझोर दिया। मध्य कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में एक बच्चे सहित नौ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। यह दुखद घटना सुबह तड़के करीब 2 बजे घटी, जब लोग गहरी नींद में थे। आग होटल के ठीक बगल में एक फायर स्टेशन के पास लगी थी, बावजूद इसके दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, आग लगने के बाद पूरे होटल में घना धुआं भर गया। बंद कमरों में फंसे कई लोग सोते समय ही धुएं के कारण बेहोश हो गए और अंततः दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे में कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में कई बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं, जो चिकित्सीय उपचार के लिए भारत आए हुए थे। अग्निशमन विभाग ने एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि जान गंवाने वाले विदेशी नागरिक इलाज के लिए कोलकाता में रुके थे। शुरुआती जानकारी और आशंकाओं के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट या एयर कंडीशनिंग यूनिट में धमाका हो सकती है, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच जारी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने तथा राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने के कारणों और किसी भी संभावित लापरवाही का पता लगाया जा सके।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने कोलकाता अग्निकांड में जानमाल की हानि पर जताया दुख

नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोलकाता के फ्री स्कूल स्ट्रीट इलाके में मंगलवार देर रात एक होटल में आग लगने से नौ लोगों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने बुधवार को कोलकाता अग्निकांड में हुई जानमाल की हानि पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में आग लगने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने शोक संपत्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा: अमेरिकी राजदूत

आर्टिकल 370 हटने के बाद अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा, सीएम उमर से मिले

श्रीनगर। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा, 'मैं पहली बार इस जगह का दौरा कर रहा हूं। यह खूबसूरत जगह है।' धारा 370 हटने के बाद यह किसी अमेरिकी राजदूत का पहला दौरा है। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की। इसके साथ ही गोर ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ की। उन्होंने कहा, 'नई दिल्ली और स्थानीय सरकार ने इसके लिए बहुत काम किया है। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को जारी होने वाली ट्रैवल एडवाइजरी में वह इस बात का ख्याल रखेंगे।' हालांकि, गोर ने इसे लेकर कोई घोषणा नहीं की।

धारा 370 हटने के बाद यह पहला अमेरिकी दौरा : राज्य में धारा-370 हटने के बाद किसी भी अमेरिकी राजदूत का यह पहला आधिकारिक दौरा है। हालांकि, इससे पहले 9 जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर 15 देशों के सरकारी डेलिगेशन के साथ कश्मीर गए थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'हमारी बैठक बहुत अच्छी रही। हमें दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा करने का मौका मिला, लेकिन विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि अमेरिका जम्मू और कश्मीर के मामले में क्या कर सकता है। कुछ पुराने मुद्दे हैं जिन्हें हम समय के साथ सुलझाने का प्रयास करेंगे।

होर्मुज पर तनाव बढ़ा, अमेरिकी सहयोगियों से ईरान खफा

यूएई के समुद्री नौवहन पर हमले से खलबली, रुबियो ने एनएसए से की बात

एजेंसी। अबूधाबी/वाशिंगटन/तेहरान

लगभग सात माह से सैन्य टकराव और तनाव के बादलों से घिरे होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थिति और गंभीर हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह के कभी बनते और बिगड़ते प्रयासों के बीच संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) पर हुए हमले के बाद होर्मुज की सुरक्षा को लेकर मध्य क्षेत्र में खलबली मच गई है। ईरान इस समय अमेरिका के सहयोगी देशों के खेमे से खफा है। उसने यूएई के समुद्री नौवहन को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाकर अपना रुख साफ कर दिया है। इसके बाद अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो ने यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) शेख तहनून बिन ज़ायद अल नाहयान से क्षेत्र की अहम सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा की है। अल जजीरा, गल्फ न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बड़ा कदम उठाया है। यूएई ने आज तत्काल प्रभाव से ईरान के साथ सभी तरह के व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी। यूएई ने यह कदम क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता, क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए उठाया है। यूएई विदेश मंत्रालय के रणनीतिक संचार विभाग की निदेशक अफरा अल हमेली ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये प्रतिबंध अगली सूचना तक लागू रहेंगे। मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। होर्मुज जलडमरूमध्य अब अमेरिकी क्षेत्र में है। ट्रंप ने इस जलमार्ग को नया अमेरिकी क्षेत्र बताने वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की है। ईरान ने जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए अपनी शर्तें दोहराई हैं। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि व्यापक यूएस-ईरान बातचीत फिर से शुरू होने से पहले मध्यस्थ होर्मुज पर ईरान-ओमान के बीच द्विपक्षीय समझौते का इंतजार कर रहे हैं। यूएई पर हमले के बाद अमेरिका के विदेश सचिव रुबियो ने यूएई के एनएसए शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान से टेलीफोनिक बातचीत में होर्मुज जलडमरूमध्य में आवाजाही की आजादी बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट के अनुसार, रुबियो ने प्रमुख क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान से बात की है। इस दौरान दोनों ने लेबनान के हालात पर भी चर्चा की। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने यूएई के रक्षा मंत्रालय के दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागने के दावे को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों से पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों को नुकसान पहुंचता है और क्षेत्र में आपसी भरोसे को ठेस पहुंचती है। उधर, ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दुल्लाही ने खाड़ी देशों को अमेरिकी सेना की मदद न करने की चेतावनी दी है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के एक बयान में अब्दुल्लाही ने कहा कि इलाके के बेस पर इतने सारे मिलिट्री एयरक्राफ़्ट, खासकर रीफ़्यूलिंग करने वाले विमानों की मौजूदगी को मेजबान देशों की जानकारी के बिना समझाना मुश्किल होगा।

संक्षिप्त समाचार

तमिलनाडु के महाबलीपुरम में गुरुवार को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक, अमित शाह करेंगे अध्यक्षता

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुरुवार को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद् में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 से 22 के तहत देश में पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। दक्षिणी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष सदस्य राज्यों में से किसी एक के मुख्यमंत्री होते हैं। इस बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय उपाध्यक्ष होंगे। बैठक गृह मंत्रालय के अंतर-राज्य परिषद सचिवालय द्वारा तमिलनाडु सरकार की मेजबानी में आयोजित की जा रही है। इसमें सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, प्रशासक, प्रत्येक राज्य से दो वरिष्ठ मंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर टीम भारत की अवधारणा रखी है और क्षेत्रीय परिषदें इस दिशा में अहम योगदान दे रही हैं। परिषदें राज्यों और केंद्र के बीच संवाद और सहयोग का मंच प्रदान करती हैं। मोदी के नेतृत्व में परिषद की बैठकें संवाद से समाधान का सशक्त माध्यम बनी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जून 2014 से पिछले बारह वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 69 बैठकें आयोजित हुई हैं।

ईडी का जौहर ट्रस्ट-यूनिवर्सिटी मामले में रामपुर, सहारनपुर, दिल्ली में 10 स्थानों पर छापा

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के रामपुर के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापा मारा। ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में यह कार्रवाई की। ईडी की यहजांच सरकारी ठेकों की रकम को कथित तौर पर निजी ठेकेदारों के माध्यम से डायवर्ट किए जाने और बाद में उस धनराशि के ट्रस्ट एवं विश्वविद्यालय से जुड़ी परिसंपत्तियों और निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किए जाने से संबंधित है। ईडी के मुताबिक, जांच में कुछ निजी ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन-देन सामने आए हैं। जांच एजेंसी को यह भी जानकारी मिली है कि इसमें कथित तौर पर बड़ी रकम के दान और निर्माण कार्यों से जुड़े भुगतान शामिल हैं। एजेंसी इन लेन-देन के स्रोत, प्रवाह और अंतिम इस्तेमाल की जांच कर रही है। ईडी की टीमें वित्तीय रिकॉर्ड, दस्तावेज, बैंकिंग लेन-देन और डिजिटल साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। ईडी के अनुसार, रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट, जौहर नगर और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, जौहर नगर को कार्रवाई के दायरे में रखा गया। इसके अलावा रामपुर में एमएस ए एंड एस एंटरप्राइजेज, शौकत अली रोड, इलाही मस्जिद के सामने, थाना सिविल लाइंस क्षेत्र में भी तलाशी ली गई। रामपुर में ही एमएस सीके एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्वाला पैलेस, पीपल टोला स्थित परिसर पर भी ईडी ने कार्रवाई की।

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 200 ईवी बसों, 'लेडीज स्पेशल बस सेवा' को दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 200 नई इलेक्ट्रिक बसों, दिल्ली-करनाल अंतरराज्यीय ईवी-बस सेवा और लेडीज स्पेशल बस सेवा का हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के राजघाट डिपो-I में ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया। यह ईवी चार्जिंग स्टेशन लगभग 5.50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, स्थानीय विधायक सूर्य प्रकाश खत्री मौजूद रहे। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'शक्ति की सप्त-धारा' की सोच से प्रेरित ये पहल सस्टेनेबल मोबिलिटी को मजबूत करती हैं और साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा को भी बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित इन 'लेडीज स्पेशल बसों' में पैनिक बटन भी होंगे जो सीधे दिल्ली पुलिस की 112 पीसीआर सेवा से जुड़े होंगे, जिससे आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद मिल सकेगी। उपराज्यपाल ने कहा कि 'ईज ऑफ लिविंग', सस्टेनेबल मोबिलिटी और 'विकसित भारत 2047' की राह पर एक साफ-सुथरे, हरे-भरे और सुरक्षित विकसित दिल्ली की दिशा में यह एक अहम कदम है। उल्लेखनीय है कि 200 नई ईवी बसों के डीटीसी के बेड़े में शामिल होने से बसों की कुल संख्या लगभग 6800 हो गई है, जिसमें 4938 इलेक्ट्रिक बसें और 1750 सीएनजी बसें शामिल है।

साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क में शामिल आरोपित को सीबीआई ने दबोचा

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दक्षिण-पूर्व एशिया के स्कैम कम्पाउंड से जुड़े मानव तस्करी और साइबर स्लेवरी नेटवर्क में शामिल आरोपित हिसार निवासी अंकित को यहां से गिरफ्तार किया है। उसे दक्षिण-पूर्व एशिया के स्कैम कम्पाउंड से जुड़े साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक जांच में सामने आया है कि आरोपित ने साल 2025 में हिसार इलाके से कम-से-कम चार लोगों को म्यांमार और कंबोडिया के स्कैम कम्पाउंड भेजा था। वहां उन्हें नौकरी के झूठे वादों के जरिए फंसाया गया और बाद में भारी रकम देकर या किसी और को फंसाकर ही वे वापस लौट पाए। सीबीआई ने आरोपित के मोबाइल से कई अहम सबूत बरामद किए हैं। इनमें म्यांमार और कंबोडिया के स्कैम कम्पाउंड संचालकों से उसकी बातचीत, सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर डाले गए विज्ञापन और टेलीग्राम पर हुई चैट शामिल हैं। इसके अलावा कई क्रिप्टो करेंसी लेन-देन भी सामने आए हैं, जिन्हें कमीशन के तौर पर बताया जा रहा है।

सीबीआई ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उप लेखा नियंत्रक को 10 लाख रुपये घूस लेते पकड़ा

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत उप लेखा नियंत्रक संदीप को 10 लाख रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने एक निजी कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण की फाइल को जल्द निपटाने के लिए पहले 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। बातचीत के बाद वह 10 लाख रुपये लेने पर सहमत हुआ। सीबीआई के अनुसार, आरोपी उप लेखा नियंत्रक संदीप (आईसीएएसः 2020) के खिलाफ मंगलवार को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। वह यहां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि निजी कंपनी के अनुबंध के नवीनीकरण से जुड़ी फाइल उसके पास लंबित थी और उसे जल्द निपटाने के लिए आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी।

रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्री अपने जापानी समकक्ष के साथ नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त, 2026 को नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री श्री शिंजीरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने तथा सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान किए जाने की आशा है। जापान द्वारा रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तीन सिद्धांतों में संशोधन के बाद, दोनों मंत्री 'मेक-इन-इंडिया' प्रारूप के अंतर्गत गहन समुद्री सुरक्षा सहयोग और रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। यह बैठक द्विपक्षीय रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार करने का अवसर प्रदान करती है। भारत की अपनी पहली यात्रा पर आए श्री शिंजीरो कोइजुमी ने 19 अगस्त, 2026 को मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया, जहां उन्होंने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के ध्वज अधिकारी कमान प्रमुख वाइस एडमिरल संजय वत्सयान के साथ चर्चा की।

दविंदर बंबीहा गैंग के 3 वांटेड सदस्य मलेशिया से डिपोर्ट

पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया गिरफ्तार

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस विंग के ओवरसीज फ्यूजिटिव ट्रैकिंग एंड एक्सट्रैडिशन सेल (ओएफटीईसी) ने केंद्रीय एजेंसियों की मदद से दविंदर बंबीहा गैंग से जुड़े तीन वांटेड सदस्यों को मलेशिया से डिपोर्ट करवाया है। यह जानकारी पंजाब डीजीपी की ओर से एक्स पर पोस्ट कर दी गई। पंजाब पुलिस ने बताया कि इन तीनों लोगों पर हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने और लुधियाना में एक सुनियोजित हैंड-ग्रेनेड धमाके (जिसके तार पाकिस्तान की आईएसएआई से जुड़े थे) जैसे कई मामलों में आरोप हैं। आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ जस बेहबल, अजय सिंह और पवनदीप सिंह को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच के लिए उसे पंजाब लाया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रही है।

बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र के 8 जिलों में फैली 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी

एजेंसी। नई दिल्ली

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में फैली 4 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की लंबाई जुड़ जाएगी। कुल अनुमानित लागत 9,450 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 6,448 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनकी आबादी लगभग 60 लाख है। नई रेल लाइनें इस प्रकार हैं- पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खड़गपुर-भद्रक (रानीताल) चौथी लाइन (173 किमी), ओडिशा में भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन (75 किमी), आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गुम्मिडिपुंडी-गुदुर तीसरी और चौथी लाइन (90 किमी), ओडिशा में कटक-पारादीप (बड़ाबांधा) तीसरी और चौथी लाइन (72 किमी)। केन्द्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुधवार को राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देशभर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, लोहा और इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल, अनाज आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। क्षमता वृद्धि कार्यों से प्रति वर्ष 76 मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन माध्यम होने के कारण जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में सहायक होगा।

बिहार में स्कूल का हिस्सा गंडक में बहा, हिमाचल-उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 6 मौतें

लगातार बारिश से कई राज्यों में हालात बिगड़े, प्रयागराज में घरों में घुसा पानी

एजेंसी। नई दिल्ली

देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार तीसरे दिन बारिश के चलते कई निचले इलाकों में घरों के भीतर पानी भर गया। पानी इतना बढ़ गया कि बेड, सोफा और अन्य घरेलू सामान डूब गए। जिले में लगातार दूसरे दिन सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। रामबाग रेलवे स्टेशन के तीन रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए, जिससे रेल संचालन प्रभावित हुआ है। बिहार के बगहा में गंडक नदी के तेज कटाव ने एक प्राथमिक स्कूल को अपनी चपेट में ले लिया। स्कूल के पांच में से चार कमरे नदी में बह गए। बचा हुआ हिस्सा भी कटाव के खतरे में है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश के दौरान लैंडस्लाइड से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक ट्रक चालक और नेपाल के दो मजदूर शामिल हैं।

यूपी के 13 जिलों में बाढ़, 84 हजार से अधिक प्रभावित : उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के 173 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 13,058 हेक्टेयर क्षेत्र और 84,362 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन अब तक 4,800 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुका है।

असम में पुल टूटने से बच्चों की मुश्किल बढ़ी : असम के जोनाई में पुल टूटने के बाद से ही स्कूली बच्चों को नदी पार कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई छात्र तो नाव नहीं मिलने के चलते पैदल नदी पार करते देखे गए हैं, जिससे उनके कपड़े और किताबें तक भीग जाती हैं।

हरियाणा में 16 जिलों में बारिश का अनुमान : हरियाणा में मानसून फिर सक्रिय है। प्रदेश के 16 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मंगलवार को पंचकूला में तेज बारिश के बाद घग्गर सहित कई नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया।

ओम बिरला के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर किया नमन

नई दिल्ली। महाकवि एवं भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने उन्हें नमन किया। उन्होंने लोकभाषा के माध्यम से भक्ति को जन-जन तक पहुंचाने और भगवान श्रीराम के आदर्शों को भारतीय जनमानस के जीवन-मूल्यों से जोड़ने वाले तुलसीदास के योगदान को याद किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तुलसीदास को नमन करते हुए कहा कि उनकी अमर रचना 'श्रीरामचरितमानस' में मर्यादा, करुणा, त्याग, सत्य, कर्तव्य और धर्म का ऐसा समन्वय है, जो हर युग में मनुष्य को जीवन की सही दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने संस्कृत की गूढ़ आध्यात्मिक चेतना को लोकभाषा की सरलता और सरसता में ढालकर भक्ति को जन-जन तक पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुलसीदास की पंक्तियां "जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई" साझा करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि 'श्रीरामचरितमानस' के माध्यम से तुलसीदास ने सत्य, मर्यादा, करुणा, कर्तव्य और लोककल्याण की राह दिखाई।

डीजेबी के एसटीपी घोटाले में 16 करोड़ की मनी ट्रेल का दावा

नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के टेंडर में कथित हेरफेर की जांच में एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) को कई अहम सुराग मिले हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि पांच एसटीपी के अपग्रेडेशन वाले टेंडर में क्षमता बढ़ाने यानी ऑगमेंटेशन की लागत भी जोड़ दी गई, जबकि वहां केवल अपग्रेडेशन होना था। इससे तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनी को कथित तौर पर फायदा पहुंचा। जांच में करीब 16 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल मिलने और टेंडर प्रक्रिया से जुड़े चैट व दस्तावेज बरामद होने का भी दावा किया गया है। मामले में एसीबी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, डीजेबी के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों में डीजेबी के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, एएन एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरनमेंट प्रा.लि. के मालिक राज कुमार कुर्रा और सृजनहार के प्रोपराइटर पंकज वर्मा शामिल हैं। जांच एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों की भूमिका कथित टेंडर हेरफेर में सामने आई है।

सम्पादकीय

नबीन के नगीने

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नये बदलाव के जरिये एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। कार्यकारिणी में उ.प्र. के पदाधिकारियों का दबदबा, अपेक्षाकृत युवाओं को तरजीह तथा आईटी सेल के शीर्ष पद में बदलाव बताता है, ये परिवर्तन समय की जरूरत है। कहीं न कहीं जेन-जी आंदोलन के बाद पार्टी ने बदलाव की आकांक्षी नई पीढ़ी से जुड़ने का मन बनाया है। छात्र आंदोलन में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका को महसूस करते हुए एक दशक के बाद भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय की विदाई हुई है और दीपक म्हस्के की एंट्री हुई है। कैमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे म्हस्के चुनावी आंकड़ों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संबंधित डेटा विश्लेषण अभियान से जुड़े रहे हैं। छत्तीसगढ़ आईटी सेल के समन्वयक रहे म्हस्के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और विभिन्न क्षेत्रों में व्हाट्सऐप समूहों का नेटवर्क तैयार करने के लिये पहचान रखते हैं। दरअसल, पार्टी वार-प्रतिवार के दौर से आगे निकलकर क्षेत्र, आयु समूह व मुद्दों के जरिये जनता का मूड भांपने का प्रयास करेगी। निस्संदेह, यह निर्णय राजनीति में सोशल मीडिया की बदलती भूमिका को भी दर्शाता है। पार्टी ने महसूस किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ प्रचार का जरिया ही नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक असंतोष से मुकाबले तथा आम लोगों से जुड़ने का भी माध्यम बना है। पार्टी ने यह भी महसूस किया कि हालिया छात्र आंदोलन में छोटे वीडियो, व्यंग्य, राजनीतिक मीम व वायरल सामग्री की लोगों को जोड़ने में बड़ी भूमिका रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उ.प्र. में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उ.प्र. का दबदबा नजर आता है। जिन आठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनमें राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी सुर्खियों में है। साथ ही राजनीतिक समीकरण साधने के लिये ओबीसी से लेकर अल्पसंख्यक चेहरे कार्यकारिणी में उ.प्र. से शामिल किए गए है। कह सकते हैं राजनीति के साथ ही सामाजिक समीकरण भी साधने की कोशिश हुई है। बहरहाल, नितिन नबीन की नई कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी ने खासी सुर्खियां बटोरी हैं क्योंकि अमेठी से चुनाव हारने के बाद उन्हें हाशिये पर माना जा रहा था। एक समय राहुल गांधी को हराकर अमेठी से सांसद और मंत्री बनने के बाद वे लगातार सुर्खियों में रही थीं। वहीं कुर्मी समाज से आने वाली रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं दलित समुदाय से आने वाले बुलंदशहर के सांसद डॉ.भोला सिंह राष्ट्रीय सचिव, प्रभावी यादव समाज से आने वाली आजमगढ़ की संगीता यादव के जरिये आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हुई है। उत्तर प्रदेश से ही अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी ओर उ.प्र. के ही कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान दी गई है। जो संगठनात्मक रणनीति के साथ ही इन समाजों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी है। इसे उ.प्र. में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी माना जा रहा है। निस्संदेह, यह कहावत सटीक है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उ.प्र. से होकर ही जाता है। यही वजह है कि भाजपा के लिये प्रदेश का विधानसभा चुनाव प्रतिष्ठा का प्रतीक बनना स्वाभाविक ही है। दूसरी ओर भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में संघ से जुड़े रहे राम माधव, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे तीरथ सिंह रावत व बैजयंत जयपांडो जैसे दिग्गज नेताओं को तरजीह मिली है। वहीं युवाओं को प्राथमिकता देने के क्रम में युवा मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में हेमांग जोशी के नाम की चर्चा हो रही है। दूसरी तरफ पार्टी ने राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पीयूष गोयल को दी है। वहीं नॉर्थ ईस्ट कॉर्डिनेटर पद पर संबित पात्रा व मीडिया संयोजक के पद पर अनिल बलूनी दायित्व निभाएंगे। पार्टी ने महिलाओं को भी महत्व दिया है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों में कुल मिलाकर बारह महिलाएं शामिल की गई हैं। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की नेता रूप चौधरी को प्रदान की गई है।

उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा मानसून सत्र

संसदीय मर्यादाओं का क्षरण कब तक? आखिर कब हम संसद के एक-एक मिनट का उपयोग करने की पात्रता विकसित करेंगे? आजादी की 80वीं वर्षगांठ की आयोजना से पूर्व भारत में संसद का मानसून सत्र जिस निराशाजनक स्थिति, नाउम्मीदी और उपेक्षापूर्ण स्थितियां के साथ संपन्न हुआ, वह केवल किसी एक दल, सरकार या विपक्ष की विफलता नहीं है, बल्कि हमारी संसदीय संस्कृति के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। 25 दिनों तक चले इस सत्र में तीखी राजनीतिक बहस के बजाय हंगामा, नारेबाजी, गतिरोध और कार्यवाही बाधित करने की प्रवृत्ति अधिक प्रभावी रही। प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता पक्ष सही था या विपक्ष, प्रश्न यह है कि क्या हमारी संसद अपने मूल दायित्व-जनता के प्रश्नों पर गंभीर विमर्श, सरकार की जवाबदेही और राष्ट्रहित में कानून निर्माण को पूरा कर पा रही है? इस सत्र के आंकड़े स्वयं बहुत कुछ कह रहे हैं। लोकसभा की उत्पादकता बमुश्किल 19 प्रतिशत रही, जबकि राज्यसभा में लगभग 39 प्रतिशत काम हो पाया। लोकसभा में एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। यह स्थिति इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि प्रश्नकाल संसद की आत्मा माना जाता है। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सरकार से प्रश्न पूछने और सरकार को उनका उत्तर देने का अवसर ही यदि सदन में उपलब्ध न हो, तो लोकतंत्र की जवाबदेही किस रास्ते से सुनिश्चित होगी? 28 जुलाई को लोकसभा में अपेक्षाकृत ठीक काम हुआ, जबकि राज्यसभा में भी केवल कुछ दिन ही सार्थक कार्यवाही हो सकी। शेष समय का बड़ा हिस्सा राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया।

संसद केवल ईंट-पत्थर से बनी इमारत नहीं है। वह भारत की सामूहिक चेतना का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। वहां देश के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाएं, समस्याएं और सपने पहुंचते हैं। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, व्यापारी, युवा, गरीब और वंचित वर्ग-सभी की आवाज संसद के माध्यम से राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती है। इसलिए संसद का एक मिनट भी केवल सांसद का समय नहीं होता, वह देश की जनता के धन, विश्वास और लोकतांत्रिक अधिकार का समय होता है। संसद का प्रत्येक व्यर्थ गया मिनट वास्तव में जनता के विश्वास से घटा हुआ एक मिनट है। दुर्भाग्य यह है कि संसद में हंगामा अब अपवाद नहीं, बल्कि संसदीय राजनीति का लगभग नियमित हथियार बनता जा रहा है। मुद्दे उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार को घेरना विपक्ष का दायित्व है और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन असहमति को संवाद में बदलने के बजाय कार्यवाही रोक देना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। विरोध की भी एक मर्यादा होती है। यदि विपक्ष अपनी बात रखने के लिए सदन को चलने ही न दे और सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज सुनने की बजाय राजनीतिक बहुमत को ही पर्याप्त समझे, तो दोनों मिलकर संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करते हैं। इस सत्र में कुछ घटनाएं इस गिरावट को और स्पष्ट करती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के समापन पर पारंपरिक समापन भाषण नहीं दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के साथ होने वाली चाय पार्टी का बहिष्कार किया जाना भी केवल एक कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं माना जा सकता। यह सदन के भीतर बढ़ती राजनीतिक कटुता का संकेत है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, मनभेद लोकतंत्र के लिए घातक हैं। संसद में बहस के बाद हाथ मिलाने की संस्कृति विकसित होनी चाहिए, बहस के बाद दूरी बढ़ाने की नहीं। इस मानसून सत्र को नीट-यूजी पेपर लीक, जंतर-मंतर छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और राम मंदिर में दान चोरी जैसे मुद्दों के लिए भी याद किया जाएगा। जंतर-मंतर पर हुई हिंसा के बाद विपक्ष केंद्रीय गृहमंत्री से जवाब मांग रहा था। जब सत्र के अंतिम दिनों में गृहमंत्री जवाब देने को तैयार हुए तो विपक्ष द्वारा उनका वक्तव्य सुनने से इनकार करना संसदीय विवेक की कसौटी पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि विपक्ष को सरकार के जवाब से असहमति थी, तो उसे सुनकर तथ्यात्मक प्रतिवाद करना अधिक प्रभावी लोकतांत्रिक रास्ता होता। संसद में जवाब सुनने से इनकार करना प्रश्न का समाधान नहीं, प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ना है।

यह भी सच है कि तमाम गतिरोध के बीच संसद ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए को सरकार ने विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 दोनों सदनों में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाना और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बैंकिंग रिकॉर्ड को नए डिजिटल ढांचे से जोड़ने, जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को अधिक कठोर बनाने तथा अन्य विधायी एवं प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी कदम उठे। केरल का नाम विधिवत केरलम किए जाने का निर्णय भी इसी सत्र का हिस्सा रहा। ये उपलब्धियां बताती हैं कि यदि संसद चले तो कम समय में भी महत्वपूर्ण काम संभव है। लेकिन सवाल फिर वही है-जब संसद चल सकती है तो उसे बार-बार रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या हम यह भूल गए हैं कि लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव जीतना नहीं है? लोकतंत्र का

वास्तविक अर्थ है-विचारों का सम्मान, असहमति की स्वीकार्यता, संवाद की निरंतरता और निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी। सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि बहुमत उसे शासन करने का अधिकार देता है, लेकिन विपक्ष को सुनने से मुक्त नहीं करता। दूसरी ओर विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध का अधिकार संसद को निष्क्रिय करने का अधिकार नहीं है। अतीत में हमारी संसदीय परंपरा ने अनेक कठिन दौर देखे हैं। तीखी बहसें हुईं, वैचारिक संघर्ष हुए, सरकारों की आलोचना हुई, लेकिन संसद को संवाद का मंच बनाए रखने की कोशिश होती रही। आज आवश्यकता है कि हम उस परंपरा को पुनर्जीवित करें। राजनीतिक दलों को अपने भीतर यह आत्ममंथन करना होगा कि क्या वे जनता के बीच जाकर यह कह सकते हैं कि हमने संसद में आपके प्रश्नों के लिए उपलब्ध समय का पूरा उपयोग किया? क्या कोई सांसद गर्व से कह सकता है कि उसने अपने कार्यकाल के प्रत्येक संसदीय अवसर को राष्ट्रहित में लगाया? संसद में हंगामा करना आसान है, लेकिन संसद चलाना चरित्र, संयम और लोकतांत्रिक परिपक्वता मांगता है। नारे लगाने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन तथ्यपूर्ण बहस के लिए अध्ययन चाहिए। माइक के सामने खड़े होने के लिए राजनीतिक उत्साह चाहिए, लेकिन कानून बनाने के लिए दूरदृष्टि चाहिए। कार्यवाही रोकने के लिए संख्या पर्याप्त हो सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए विवेक, धैर्य और संवाद आवश्यक है। आजादी के 80वें वर्ष की ओर बढ़ते भारत के लिए यह आत्ममंथन का समय है। हमने विज्ञान, अर्थव्यवस्था, तकनीक और वैश्विक प्रतिष्ठा के अनेक क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन क्या हमारी राजनीतिक संस्थाएं भी उसी गति से परिपक्व हुई हैं? क्या हम संसदीय प्रणाली को इतना सशक्त बना पाए हैं कि संसद के एक-एक मिनट का अधिकतम उपयोग कर सकें?

क्या हम अपनी असहमति को इतनी गरिमा दे पाए हैं कि विरोध भी हो और संवाद भी बना रहे? क्या हम सत्ता को इतनी विनम्रता और विपक्ष को इतना विवेक दे पाए हैं कि दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें? इन प्रश्नों के उत्तर केवल संसद भवन के भीतर नहीं खोजे जाने चाहिए। राजनीतिक दलों के नेतृत्व, सांसदों, संसदीय कार्यप्रणाली और अंततः हम नागरिकों-सभी को इस पर विचार करना होगा। जनता को भी यह प्रश्न पूछना चाहिए कि उसका प्रतिनिधि संसद में कितनी बार उपस्थित रहा, कितने प्रश्न पूछे, कितनी बहसों में भाग लिया और राष्ट्र के लिए क्या सार्थक योगदान दिया। लोकतंत्र केवल पांच वर्ष में एक बार वोट देने से मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता अपने प्रतिनिधियों से निरंतर जवाब मांगती है। हंगामा किसी दल की विजय नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की सामूहिक पराजय है। संसद चलेगी तो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे तो सरकार जवाब देगी, जवाब मिलेगा तो नीतियों की समीक्षा होगी और सार्थक कानून बनेंगे। यही लोकतंत्र की जीवन-धारा है।

भारत में पाकिस्तानियों को मिल गई नागरिकता ?

किसी पाकिस्तानी को आज के दौर में हिंदुस्तान में बसाना, उन्हें पनाह देना या फिर नागरिकता देनी वाली बात, शायद ही किसी के गले उतरे? बसाना तो दूर, ऐसा सोचना मात्र भी, सूरज का पूरब की जगह पश्चिम से निकलने जैसा माना जाएगा। पर, यह कोरी कल्पना पिछले दिनों हकीकत में तब्दील हुई। भारत में 56 साल पहले आए पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई है। वह भी एकाध लोगों को नहीं, बल्कि हजारों को। सरकार ने पिछले महीने बकायदा एक रंगारंग कार्यक्रम कर, ढोल-नगाड़े बजाकर विस्थापित पाकिस्तानियों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे। ताज्जुब यह भी है कि ऐसा चमत्कार हुकूमत ने ऐसे माहौल में किया, जब समूचे भारत में विभिन्न देशों के घुसपैठियों को निकालकर उन्हें खदेड़ने का अभियान केंद्रीय व राज्य स्तरों पर छिड़ा हो। इस अभियान की बानगी हमने हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधाानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। जब दो बॉर्डर राज्य, असम और पश्चिम बंगाल, का चुनाव इसी मसले के इर्दगिर्द घूमा। घुसपैठियों के अलावा भारत में कुछ वर्षों से एनआरसी और सीएए का भी शोर है। बावजूद इसके सरकार ने पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का बड़ा जाखिम उठाया। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? हालांकि, इस फैसले के सियासी मायने बहुतेरे हैं, जिसकी तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई भी देगी।

सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांसुरी निमार्ण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों से नागरिकता मांगते आए हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1959 से 1971 के बीच पाकिस्तान से पीड़ित होकर कुछेक परिवार भारत आए थे। शुरूआत में यह परिवार कई राज्यों में भटकते रहे, कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बाद में यही जिला मुफीद लगा। पीलीभीत के अलावा कुछ नागरिकता रामपुर और बिजनौर में बसे विस्थापितों को भी दी गई है। पीलीभीत के जिस क्षेत्र में यह परिवार रहते आए हैं वह जगह कभी विरान होती थी। इन लोगों ने इसे रहने लायक बनाया और उबड़खाबड़ जगहों पर मेहनत करके उसे खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया। आज इस क्षेत्र में अच्छी फसलें उगती हैं। सभी के पास कागजी दस्तावेजों के रूप में भारतीय आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पहले से मौजूद हैं। साथ ही लंबे वक्त से मतदान भी करते आए हैं। लेकिन नागरिकता और मालिकाना हक से वंचित थे, जिसे मौजूदा योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये परिवार पीलीभीत जिले के अमरिया, न्यूरिया, शारदा डैम की तलहटी सहित आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। सरकार ने उन्हें खेती और आवास के लिए जमीन तो पहले से दी हुई हैं। लेकिन मालिकाना हैसियत नहीं दी, जिसके लिए यह लोग दशकों जद्दोजहद कर रहे थे। प्रत्येक चुनावों में इनसे के झूठा आश्वासन हुआ। पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने भी इनको नागरिकता दिलवाने का दिलासा दिया।

पर, कुछ राजनैतिक अड़चनों के चलते वादा पूरा नही कर पाए।

बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ वादा किया गया था, जिसे अब पूरा किया गया। प्रदेश सरकार की पहल पर सभी पीड़ित परिवारों को सूचीबद्ध करके नागरिकता और मालिकाना के प्रमाण बांटे गए हैं। नागरिकता करीब 2500 परिवारों को दी गई हैं जिनकी कुल संख्या 15 हजार के आसपार है। ऐसा करके सरकार ने शायद विपक्षी दलों को बड़ा सियासी मुद्दा बैठे-बिठाए थमा दिया है। ये लोग वर्ष 1960 से 1975 के बीच धार्मिक प्रताड़ना के चलते पूर्वी बंगालादेश जो अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, से भारत आए थे और उत्तर प्रदेश के तराई के जिले पीलीभीत में आकर बसे। ये क्षेत्र पीलीभीत जिले की कलीनगर व पूरनपुर तहसीलों में आते हैं जहां ये करीब 25-26 गांवों में बसे हैं। पिछले महीने 29 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में दौरा हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने इनको ना सिर्फ नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे, बल्कि मालिकाना हक के सरकारी कागज भी दिए। यह फैसला चुनाव के ऐन वक्त लिया गया। प्रदेश में मात्र 6-7 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश की राजनीति जमकर गर्माई हुई है। विपक्षी पार्टियों ने सीधे-सीधे एक बड़े वोटबैंक को साधने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाया है। पाकिस्तानी विस्थापियों को बसाने का यह पहला चरण है, अभी दूसरा चरण शेष है। 35 हजार लोग और हैं जो बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर, बिजनौर जैसे जिलों में बसे हैं।

विशेष आलेख /राशिफल

फिर से पटरी पर आता बंगाल

किसी सरकार के जीवन में सौ दिन बहुत लंबा समय नहीं होता, लेकिन सौ दिन यह बताने के लिए पर्याप्त होते हैं कि सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है और दिशा क्या है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले सौ दिन इसी कसौटी पर देखे जाने चाहिए। इन सौ दिनों में सबसे बड़ा परिवर्तन बंगाल के माहौल में दिखाई देता है। लंबे समय बाद बंगाल में आम आदमी यह महसूस कर रहा है कि सरकार केवल सत्ता का प्रतिष्ठान नहीं, उसकी अपनी सरकार भी है। कानून सबके लिए है। प्रशासन को जवाबदेही तय करनी होगी। बंगाल लंबे समय तक राजनीतिक हिंसा, टकराव और भय की खबरों से पहचाना जाता रहा।

गांव से शहर तक राजनीति जीवन के हर हिस्से में मौजूद थी। नई सरकार के सामने पहली चुनौती इसी माहौल को बदलने की थी। सत्ता परिवर्तन का अर्थ केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों का बदलना नहीं होता। असली परिवर्तन तब होता है, जब शासन की कार्यसंस्कृति बदलती है। इन सौ दिनों में सरकार ने प्रशासन को स्पष्ट संकेत दिया है कि अब जवाबदेही सर्वोपरि है। फैसले समय पर हों। जनता की शिकायतें सुनी जाएं। योजनाएं कागज से निकलकर जमीन तक पहुंचें। बंगाल सरकार ने शुरुआती सौ दिनों में स्वास्थ्य, रोजगार, महिला कल्याण, सीमा सुरक्षा और केंद्र-राज्य सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। नई सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को राज्य में लागू करना प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समझौता कर इस योजना से जुड़ाव हुआ। इसका महत्व केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। बंगाल का पात्र व्यक्ति देश के दूसरे हिस्से में सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकता है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए गंभीर बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं, आर्थिक संकट भी बन जाती है। इसलिए यह फैसला आमजन को स्वास्थ्य सुरक्षा और भरोसा देने वाला है। बंगाल की बांग्लादेश के साथ लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसलिए सीमा सुरक्षा यहां केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं है। इसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी, कानून-व्यवस्था और सीमावर्ती नागरिकों की सुरक्षा से है। नई सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को आवश्यक लंबित भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में निर्णय लिया। यह एक राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश भी था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होगी। बंगाल पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। पूर्वोत्तर भारत से उसकी स्वाभाविक कड़ी है। बंगाल की खाड़ी उसे दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़ती है। इस भौगोलिक सामर्थ्य को आर्थिक शक्ति में बदलना होगा।

एक समय बंगाल भारत की औद्योगिक शक्ति था। हुगली के किनारे कारखानों की कतार थी। जूट उद्योग था। इंजीनियरिंग थी। कोलकाता देश के व्यापारिक केंद्रों में अग्रणी था। दुर्गापुर और आसनसोल औद्योगिक पहचान रखते थे। हल्दिया का अपना महत्व था। फिर धीरे-धीरे उद्योगों का पलायन शुरू हुआ। नई सरकार ने अपने शुरुआती दिनों में उद्योग जगत को एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया कि अब बंगाल उद्योग से संघर्ष नहीं करेगा। निवेश केवल घोषणाओं से नहीं आता। निवेशक को भरोसा चाहिए। नीति में स्थिरता चाहिए। कानून-व्यवस्था चाहिए। जमीन और बिजली चाहिए। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सरलता चाहिए। सरकार के सामने अब चुनौती इस भरोसे को वास्तविक निवेश में बदलने की है।

बंगाल के पास आज भी अपार संभावनाएं हैं। बंदरगाह हैं। रेल नेटवर्क है। विशाल बाजार है। कुशल मानव संसाधन है। इन सभी शक्तियों को एक सूत्र में जोड़ दिया जाए तो बंगाल फिर भारत के औद्योगिक मानचित्र पर अपना पुराना गौरव प्राप्त कर सकता है। रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से पैदा नहीं होगा। एमएसएमई चाहिए। स्टार्टअप चाहिए। आइटी चाहिए। मैन्यूफैक्चरिंग चाहिए। पर्यटन चाहिए। कृषि आधारित उद्योग चाहिए। हर जिले की पहचान को रोजगार से जोड़ना आने वाले पांच वर्षों में सरकार की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होगी। बंगाल ने बीते वर्षों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कई ऐसी घटनाएं देखीं, जिन्होंने पूरे देश को विचलित किया। नई सरकार ने महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है।

महिला सुरक्षा ऐसा विषय है, जिस पर सौ दिनों की उपलब्धि गिनाकर रुकना संभव नहीं है। यह निरंतर चलने वाली जिम्मेदारी है। सौ दिनों में यदि कोई एक परिवर्तन सबसे अधिक महसूस किया जा रहा है तो वह इसी भरोसे की वापसी है। इसे आंकड़ों में नहीं मापा जा सकता। राज्य तभी आगे बढ़ता है, जब नागरिक को विश्वास हो कि उसका आने वाला कल आज से बेहतर होगा।

बंगाल चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र की धरती है। सुभाषचंद्र बोस और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कर्मभूमि है। नए बंगाल को आधुनिक बनना है, लेकिन अपनी जड़ों को छोड़कर नहीं।

क्या कहते है आपके सितारें....?

मेष
आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उनके मन में कोई डर नहीं रहेगा। यदि पैसों से जुड़ी कोई समस्या आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उसका समाधान मिलेगा।

सिंह
आपको कुछ ऐसे माध्यमों से धन लाभ होता दिख रहा है, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। आप अपने किसी पुराने मित्र से मिलकर प्रसन्न होंगे।

धनु
आज का दिन आपके लिए अत्यंत लाभदायी रहेगा। परिवार में भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन मित्रों से कुछ मतभेद रहेंगे। आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी करने भी जा सकते हैं।

वृषभ
आज का दिन आपके लिए सामान्य लाभ वाला रहेगा। आज आपको किसी खास मामले में जीत मिल सकती है जिसके लिए आप काफी समय से प्रयास कर रहे थे।

कन्या
आज का दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि लाएगा। आज युवाओं को करियर से जुड़ी कोई नई जानकारी मिलेगी और कोई अच्छी नौकरी भी मिल सकती है।

मकर
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आपका जीवनसाथी आपसे नाराज़ हो सकता है जिसके कारण आपको उसकी कोई ग़लत बात माननी पड़ सकती है।

मिथुन
गणेशजी कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको अपने अधूरे कामों का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो वे आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं।

तुला
आज का दिन आपके लिए उत्साह से भरा रहने वाला है। आप अपने हुनर और साझेदारी से किए गए काम में अच्छा पैसा कमाएंगे और लोगों का प्यार भी लूटेंगे।

कुंभ
आज का दिन आपके लिए मध्यम फलदायी रहेगा। आपको अपनी कुछ घरेलू जिम्मेदारियों को भी समझना होगा और उन्हें समय पर पूरा करना होगा।

कर्क
जीवनसाथी के सहयोग से आपको कोई संपत्ति मिल सकती है। ईश्वर की कृपा से आपके बहुत सारे काम बनने की पूरी उम्मीद है, लेकिन यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसे खत्म करने का प्रयास आपको करना होगा।

वृश्चिक
आज का दिन आपके लिए परेशानियों भरा रहेगा। आपको किसी भी बात को दिल पर लेने से बचना होगा, अन्यथा आप लोगों से नाराज रहेंगे।

मीन
आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि यदि आपके ऊपर कानून में कोई मुकदमा चल रहा है तो आज उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे चुकाना आपके लिए मुश्किल होगा।

लोकार्पण-शिलान्यास मुख्यमंत्री ने लगभग 3,500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

71 पीएम ई-बसों का शुभारंभ, जयपुर-भीलवाड़ा की 24 ई-बस, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर की 47 ई-बस शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ काम कर रही डबल इंजन सरकार- मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मूलमंत्र के साथ ही डबल इंजन सरकार ग्रीन और क्लीन एनर्जी की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-शिलान्यास करने के साथ 71 पीएम ई-बसों को रवाना किया गया है। ये विकास कार्य एवं परियोजनाएं विकसित राजस्थान-2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगी। मुख्यमंत्री एचसीएम रीपा में प्रदेशवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण मुक्त भविष्य की मजबूत नींव बन चुकी है। चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार, ऑटो इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम और पीएम ई-ड्राइव जैसी पहल से ईवी इकोसिस्टम सुदृढ़ हो रहा हैं। यही कारण है कि वर्ष 2016 के बाद से देश में ईवी की बिक्री लगभग 46 गुना बढ़ी है।

मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों को सौगातें: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विभिन्न शहरों के लिए लगभग 3 हजार 500 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

उन्होंने कुल 71 पीएम ई-बसों का शुभारंभ भी किया, जिनमें जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई-बसों का जयपुर से

तथा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर की 47 ई-बसों का वर्चुअल शुभारंभ शामिल है। कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत एक लाख 32 हजार 421 श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को 154 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। श्रमिकों को डिजिटल गैस डिटेक्टर एवं फायर रेस्क्यू किट वितरित किए गए।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

कन्वर्जेंस बैठक आयोजित

राजीविका की बहुआयामी गतिविधियों में प्रभावी कन्वर्जेंस से महिलाओं को मिलेगा व्यापक लाभ

ग्रामीण विकास शासन सचिव की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं को राजीविका से जोड़ने पर मंथन

जयपुर(नि.सं.)। ग्रामीण विकास विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में सचिवालय में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से संबंधित सभी विभागों की कन्वर्जेंस बैठक आयोजित हुई। बैठक में राजीविका की विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न विभागों की योजनाओं के बीच प्रभावी समन्वय के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय एवं आजीविका के अवसर बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राज्य के 25 लाख लखपति दीदी के लक्ष्य की दिशा में सम्बन्धित विभागों के साथ प्रभावी कन्वर्जेंस के माध्यम से 6,78,461 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में विकसित करने के रोडमैप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। श्री कुणाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं का लाभ राजीविका से जुड़ी महिलाओं और उनके स्वयं सहायता समूहों तक प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से पहुंचाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य किया जाए। बैठक में कृषि विभाग से संबंधित कन्वर्जन्स के अंतर्गत नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 2,666 कृषि सखियों की सहभागिता, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 50 ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के साथ 10 एफपीओ के माध्यम से प्रमाणित बीज उत्पादन तथा मसाला एवं मिलेट आधारित उद्यमों के प्रशिक्षण पर विस्तार से चर्चा की गई।

न्यूज इन बॉक्स

वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर की चैंपियन अनाहत सिंह ने किया बीकानेर हाउस में तीज मेले का भ्रमण

जयपुर(नि.सं.)। वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर की वर्ल्ड चैंपियन और भारत की युवा स्क्वैश स्टार अनाहत सिंह ने नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में आयोजित तीज मेले का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मेले में राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधानों और खान-पान से जुड़े विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। अनाहत सिंह ने मेले में उपस्थित कलाकारों, शिल्पकारों एवं प्रतिभागियों से बातचीत की और उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने मेले के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में विजेता बच्चे बच्चियों को प्राइज बांटे और अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए ताकि देश का नाम रोशन कर सके। रोहित कुमार ने बताया कि जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी का खिताब अपने नाम करने वाली अनाहत सिंह ने मेले में राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक कला की विविधता की सराहना करते हुए कहा कि तीज जैसे सांस्कृतिक आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने के साथ-साथ देश की विविध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान की केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री द्वारा सराहना

जनभागीदारी को बताया राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम

जयपुर(नि.सं.)। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने के उद्देश्य से श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प की केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सराहना की। केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान ऑपरेशन सीमा के सह-प्रभारी विक्रम ज्याणी व श्री गंगानगर जिले की नशा मुक्त अभियान की ब्रांड एंबेसडर लक्ष्या ज्याणी को उनके द्वारा जागरूकता के लिए किए गए 860 नाटकों के लिए सम्मानित करते हुए कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती है।

कोटा में दौड़ी पीएम ई-बसें, शहर के 3 मार्गों पर शुरू हुआ संचालन

कम किराया,अधिक सुविधा और प्रदूषण मुक्त सफर : शिक्षा मंत्री

जयपुर(नि.सं.)। कोटा शहरवासियों को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सौगात मिल गई। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत कोटा में शुरू हुई गुलाबी रंग की ई-बसों को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, संभागीय आयुक्त श्री अनिल कुमार अग्रवाल, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष श्री राकेश जैन, जिला कलक्टर एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री पीयूष समारिया तथा नगर निगम आयुक्त एवं कोटा बस सर्विस लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा ने बसों को हरी झंडी दिखाई।

जैसे ही ई-बसें शहर की सड़कों पर उतरीं, लोगों की नजरें इन पर टिक गईं। गुलाबी रंग में सजी आकर्षक बसें शहरवासियों के बीच कौतूहल का विषय बनी रहीं। सड़क से गुजरती बसों को लोग एकटक देखते रहे और इनमें सफर करने की उत्सुकता भी नजर आई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि ये बसें कम किराए में यात्रियों को अधिक सुविधाजनक सफर उपलब्ध कराएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य देश में कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम स्तर पर लाना है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ई-बसों का संचालन शहर के पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

राजीविका राखी मेला-2026 का भव्य शुभारंभ

एसएचजी बहनों के हुनर को मिला सम्मान और बाजार

शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने किया शुभारंभ, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी ने बढ़ाया महिला उद्यमियों का उत्साह

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् (राजीविका) की ओर से 'राजीविका राखी मेला-2026' का शासन सचिवालय परिसर, जयपुर में भव्य शुभारंभ हुआ। शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग कृष्ण कुणाल ने मेले का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन के पावन पर्व को महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका से जोड़ते हुए आयोजित यह मेला 18 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक शासन सचिवालय परिसर में चलेगा। मेले में प्रदेशभर के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा अपने हुनर और मेहनत से तैयार की गई हस्तनिर्मित राखियों, स्नेह भरे उपहारों तथा विविध हस्तशिल्प, ऑर्गेनिक एवं स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की जा रही है। मेले में एसएचजी महिलाओं द्वारा तैयार की गई आकर्षक हस्तनिर्मित राखियां लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन राखियों में प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मकता, स्थानीय कला और पारंपरिक हुनर की झलक देखने को मिल रही है।

भंवरी देवी हत्याकांड: हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया

पूर्व विधायक बोले- पुलिस किसको बचा रही; SHO-DSP को हटाने की मांग

फलोदी, बिलाड़ा (वि.सं.)। फलोदी जिले के लोहावट में 27 जुलाई की रात हुई भंवरी विश्नोई की हत्या के मामले में हजारों की भीड़ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट का घेराव किया। नागौर चौराहे पर सभा के बाद हजारों लोग एक साथ नागौर रोड, नगरपरिषद, अंबेडकर सर्किल होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। लोगों की भीड़ इतनी थी कि कलेक्ट्रेट में खड़े होने की जगह नहीं बची। लोग नेशनल हाईवे और रेलवे ओवर ब्रिज पर खड़े रहे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलेक्टर अंकित कुमार सिंह और एसपी सतनाम सिंह को ज्ञापन सौंपे। लोगों ने लोहावट डीएसपी भवानीसिंह और एसएचओ हरीसिंह राजपुरोहित को हटाने की मांग की।

राजस्थान के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगी नई दिशा

सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट पर टेक्सटाइल सेक्टर से जीरो लिक्विड डिस्चार्ज पर होगा फोकस

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) द्वारा 19 अगस्त 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC), जयपुर में "Circularity in Te&tile Sector – Best Practices for Sustainability and New Technologies for Circular Economy" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यशाला 15 से 18 सितंबर 2026 तक गांधीनगर, गुजरात में आयोजित होने वाले 10वें वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम (WCEF-2026) के प्री-इवेंट के रूप में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD), अपशिष्ट प्रबंधन तथा आधुनिक पर्यावरणीय तकनीकों के साथ सतत विकास एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती अपर्णा अरोरा द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सदस्य सचिव श्री कपिल चन्द्रवाल स्वागत उद्बोधन देंगे।

तकनीकी ज्ञान, नवाचार और उद्योगों के विकास की यात्रा का साझा मंच

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चन्द्रवाल ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि कार्यशाला में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), मुंबई के विषय विशेषज्ञ, गुजरात के टेक्सटाइल विशेषज्ञ, शिक्षाविद् तथा उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा छह तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें रेडिएशन आधारित एफ्लुएंट डी-कलराइजेशन, अपशिष्ट जल उपचार की आधुनिक पद्धतियां,टेक्सटाइल केमिकल प्रबंधन, ZLD तकनीक, SCADA आधारित एफ्लुएंट मॉनिटरिंग तथा राजस्थान टेक्सटाइल क्लस्टर के सतत विकास जैसे विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

विधायक बोले- सरकारें डरी हुई है, जवाब नहीं दे रही

सांसद ने कहा- स्कूलों को सुधारने में नाकाम, उल्टे ऑर्डर निकाले

बाड़मेर(वि.सं.)। बाड़मेर कांग्रेस की 5 दिवसीय 100 किलोमीटर लंबी सद्भावना पदयात्रा का समापन मंगलवार देर शाम को गागरिया में हुआ। बीते दिनों बॉर्डर के इलाके में ऑपरेशन क्लीन चलाकर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। कांग्रेस का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर धार्मिक और व्यावसायिक अतिक्रमण तोड़कर नफरत और भय पैदा किया जा रहा है। सदियों से थार में रहे भाईचारे को कायम रखने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। अंतिम दिन हजारों की संख्या में लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया। बायतु विधायक और मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा- पदयात्रा को लोगों का कितना रिस्पांस मिला है, यह हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता है।

नाराज स्टूडेंट अजमेरी गेट पर चढ़ा

टीसी काटने से नाराज स्टूडेंट अजमेरी गेट पर चढ़ा : कूदने की धमकी दी

मां की बात भी नहीं सुनी; हाथ में था मिर्च स्प्रे

जयपुर। जयपुर में स्कूल के टीसी काटने से नाराज 12वीं क्लास का स्टूडेंट अजमेरी गेट के ऊपर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे से समझाइश की, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में पुलिसकर्मियों ने उसे बातों में उलझाकर नीचे उतारा। मामला

जालूपुरा थाना इलाके का बुधवार सुबह का है। स्टूडेंट मिर्च स्प्रे भी साथ लेकर गया था। जानकारी के अनुसार- चित्रकूट इलाके का रहने वाला स्टूडेंट सुबह 9:30 बजे अजमेरी गेट पर चढ़ा तो आसपास के लोग हैरान रह गए। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो स्टूडेंट कूदने की धमकी देने लगा। पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए स्टूडेंट को बातों में उलझाया। थानाधिकारी बृजेश सिंह ने स्टूडेंट से बात की तो उसने अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया। मोबाइल से उसकी मां को फोन करके मौके पर बुलाया गया। मां ने भी बेटे को समझाया, लेकिन वह नहीं माना।

डी-रेगुलेशन फेज-I मुख्यमंत्री के नेतृत्व में डी-रेगुलेशन फेज-I में प्रक्रियाओं के सरलीकरण से सकारात्मक परिणाम

प्रदेश मे डी-रेगुलेशन फेज-I की जुलाई माह की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जारी

- **राज्य में चार माह में 2.37 लाख करोड़ रुपये के निवेश आशय**
- **राज निवेश पोर्टल पर आवेदनों में लगभग तीन गुना वृद्धि**
- **भू-उपयोग परिवर्तन की निर्णय अवधि में 92 प्रतिशत की कमी**

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में डी-रेगुलेशन फेज-I के तहत व्यवसाय और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए जा रहे सुधारों के निरंतर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्य सचिव कार्यालय के तहत प्रदेश में डी-रेगुलेशन फेज-द्व की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए गठित सेल द्वारा जारी जुलाई माह की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई 2026 के दौरान प्रदेश में लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपये के निवेश आशय प्राप्त हुए हैं। वहीं राज निवेश पोर्टल पर आवेदनों की संख्या में लगभग तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख व्यावसायिक सेवाओं के निस्तारण में लगने वाला समय भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा व्यवसाय से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने, नियामकीय एवं अनुपालन भार कम करने तथा निवेश संबंधी स्वीकृतियों में तेजी लाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों से निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां और सेवाएं कम समय में उपलब्ध कराने में मदद मिली है। साथ ही ये सुधार

विकसित राजस्थान@2047 और विकसित भारत@2047 के विजन के अनुरूप प्रदेश को अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि डी-रेगुलेशन फेज-I की जुलाई 2026 की मासिक इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से जुलाई के दौरान राज निवेश पोर्टल पर 40 हजार 692 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 21 हजार 899 आवेदनों को स्वीकृति दी गई।

झोटवाड़ा की सड़कों को मिली रफ्तार

जनसंवाद में क्षेत्रवासियों ने जताया कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार

जयपुर(नि.सं.)।कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने मंगलम सिटी, निवारू, बोतावाल, केश्यावाला समेत झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से आए स्वजनों से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में हो रहे सड़क निर्माण एवं विकास कार्यों को लेकर खुशी व्यक्त की और अटल प्रगति पथ सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का आभार जताया। लोगों ने कहा कि लंबे समय से सड़क सुविधाओं को लेकर जिन कार्यों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, उन पर तेजी से काम होने से क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। सड़क निर्माण एवं मरम्मत के इन कार्यों से आवागमन बेहतर होने के साथ ही कॉलोनियों, गांवों और मुख्य मार्गों के बीच कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। अटल प्रगति पथ के अंतर्गत स्वीकृत सड़क कार्यों को लेकर भी क्षेत्रवासियों ने विशेष रूप से प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार जताया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा के विकास में क्षेत्र की जनता की भागीदारी और सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और सहयोग से झोटवाड़ा के विकास की यह यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर झोटवाड़ा को एक विकसित और मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाएं। जोरपुरा सुन्दरियावास रोड से शिव मंदिर, धानक्या फाटक से केश्यावाला सड़क, धानक्या फाटक से तिवारीवाला सड़क, यादव चैम्बर से श्री श्याम नरसिंह मंदिर पहाड़ी बोयतावाला वाया मंगलम विहार-डी मुख्य सड़क, चम्पापुरा से सबरामपुरा सड़क, भगवती नगर से बगीची ढाणी, निवारू, रामपुरा फाटक से पन्नाध्याय स्कीम वाया पूजा कॉलेज, रामला का बास स्कूल से कापड़ियावास सड़क,नहाथोज सिरसी लिंक रोड से जयपुरी के बाढ़ तक वार्ड नंबर 46 में मुख्य सड़क।

मुख्यमंत्री ने किया पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद

26 जिलों के 3.34 लाख किसानों को मिल रही दिन में बिजली : मुख्यमंत्री

पीएम-कुसुम योजना ने अन्नदाता को बनाया ऊर्जादाता

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की खुशहाली के लिए बीज से बाजार तक अनेक योजनाएं संचालित की है। पीएम-किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और पीएम-कुसुम जैसी पहलों से किसानों की आय सुरक्षित हो रही है। पीएम कुसुम योजना के जरिये देश का किसान अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम-कुसुम योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद करते हुए कहा कि यह योजना किसानों के लिए केवल सौर ऊर्जा योजना नहीं बल्कि अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। प्रदेश में पीएम-कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए और सी के तहत अब तक 5 हजार मेगावाट से अधिक क्षमता के 2 हजार 300 से ज्यादा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, फीडर स्तर पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक प्रदेश के किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराने का संकल्प

लिया है। वर्तमान में 26 जिलों के 3 लाख 34 हजार से अधिक किसानों को कृषि के लिए दिन में बिजली मिल रही है तथा जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार द्वारा प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 400, 220 और 132 केवी के 61 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 498 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

वहीं, 12 हजार 400 मेगावाट ऑवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। किसान सम्मान निधि की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार रुपये की गई है। किसानों को बिजली बिलों में 61 हजार करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है। साथ ही, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सौर ऊर्जा उत्पादक किसानों से संवाद कर योजना से उनके जीवन में आए बदलाव और अनुभवों पर चर्चा की। इस अवसर पर ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नगर, अधिकारी व सौर ऊर्जा उत्पादक किसान मौजूद रहे। साथ ही जोधपुर, बीकानेर और अजमेर से भी अधिकारी एवं सौर ऊर्जा उत्पादक किसान वीसी के माध्यम से जुड़े।

11वीं स्टियरिंग कमिटी की बैठक आयोजित

CAMPA की 11वीं स्टियरिंग कमिटी की बैठक आयोजित, मुख्य सचिव ने दिए दिशा-निर्देश

जयपुर(नि.सं.)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में CAMPA (क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण) की 11वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक शासन सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए अतिरिक्त वार्षिक कार्ययोजना (Supplementary Annual Plan of Operations, APO) पर विचार किया गया। समिति ने लंबित देयताओं, शेष चल रहे कार्यों (spillover works) और अन्य आवश्यक गतिविधियों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की। इस दौरान प्रस्तावित गतिविधियों और उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की विस्तृत समीक्षा की गई। विचार-विमर्श के पश्चात् समिति ने आगे की आवश्यक कार्रवाई और नेशनल CAMPA को प्रस्तुतीकरण हेतु 2026-27 की अतिरिक्त APO की अनुशंसा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि CAMPA के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग वन एवं वन्यजीव संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के लिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों की जैव विविधता को संरक्षित रखने के साथ ही वन्यजीवों के सुरक्षित आवास एवं संरक्षण के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि CAMPA के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए तथा कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। उन्होंने धनराशि के प्रभावी एवं पारदर्शी उपयोग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वन विकास एवं संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा किए जा रहे पौधारोपण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की नियमित जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए।

न्यूज ब्रीफ

150 करोड़ से सुधरेगा ड्रेनेज, झील का पानी होगा साफ

विधानसभा अध्यक्ष ने किया 7 एमएलडी के एसटीपी का लोकार्पण, अब 20 एमएलडी हुई क्षमता

जयपुर(नि.सं.)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए रीजनल कॉलेज तिराहे पर 16.31 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 7 एमएलडी क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का शुभारम्भ किया। इस प्लांट के शुरू होने से झील में उपचारित एवं साफ पानी पहुंचाने की क्षमता बढ़कर 20 एमएलडी हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत 2 योजना के तहत आनासागर झील में गिरने वाले नालों को आपस में जोड़कर प्राकृतिक ढाल एवं पम्पिंग के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना पर 22.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विशेष पहल, 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान

राज्य के विकास में योगदान देने वाले 100 प्रेरणादायी व्यक्तियों को मिलेगा नया मंच

जयपुर(नि.सं.)। राज्य के आर्थिक, औद्योगिक एवं सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रेरणादायी व्यक्तित्वों की पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के उद्देश्य से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। खास बात यह है कि 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं तथा 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों का चयन किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त श्री नीलाभ सक्सेना ने बताया कि राज्य के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्ति 31 अगस्त, 2026 तक विभाग की वेबसाइट (industries. rajasthan. gov. in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कानोड़िया गर्ल्स कॉलेज में नशा मुक्ति एवं माय भारत विषय पर हुआ जागरूकता सत्र

जयपुर। कानोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय, जयपुर में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में महाविद्यालय की राष्टीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाइयों द्वारा 'नशा मुक्ति एवं माय भारत' विषय पर युवाओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रमेश वर्मा, आईएएस, निदेशक, एनएसएस मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर नरेन्द्र गुप्ता, एस.एन.ओ., गोविन्द शरण शर्मा, जिला समन्वयक, दिनेश गुप्ता, सांख्यिकी अधिकारी तथा करिश्मा टांक, क्षेत्रीय निदेशालय युवा अधिकारी की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सीमा अग्रवाल के स्वागत उद्बोधन से हुई।

उन्होंने वनमहोत्सव को प्रोत्साहित करते हुए स्वयंसेविकाओं को पर्यावरण संरक्षण तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

गंगा जल समझौता

भारत से गंगा जल समझौते में गारंटी मांगेंगे:जरूरत पड़ी तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाएंगे:बांग्लादेश

दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश, भारत के साथ गंगा जल संधि में 'गारंटी क्लॉज' शामिल करना चाहता है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी एनी ने मंगलवार को ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। शाहिदुद्दीन ने कहा कि जरूरी हुआ तो बांग्लादेश अंतरराष्टीय मंच का रुख भी कर सकता है। दरअसल, बांग्लादेश के साथ गंगा जल संधि दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगी। इस समझौते के तहत सूखे के मौसम में गंगा के पानी के बंटवारे की व्यवस्था की गई है। ऐसे में ढाका गारंटी क्लॉज में न्यूनतम जल प्रवाह की बात शामिल करने की मांग कर रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि सूखे मौसम में जरूरत के मुताबिक पानी उपलब्ध नहीं कराती है। बांग्लादेश का कहना है कि मौजूदा संधि में पानी बांटने का फॉर्मूला तो है, लेकिन तय मात्रा में पानी मिलने की कानूनी गारंटी नहीं है। इसलिए वह नई संधि में गारंटी क्लॉज जोड़ने की मांग कर रहा है। गारंटी क्लॉज ऐसा नियम है, जो सुनिश्चित करता है कि नदी के निचले हिस्से में बसे देश को भी जरूरत का पानी मिलता रहे। इसका मतलब है कि अगर नदी में पानी कम भी हो जाए, तब भी उसे एक तय मात्रा में पानी दिया जाएगा। बांग्लादेश चाहता है कि अगर किसी साल पानी कम हो या किसी कारण से समझौते का पालन न हो, तो उसका समाधान कैसे होगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, यह भी समझौते में साफ लिखा जाए।

पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई टास्क फोर्स

50त युवाओं को चुनाव लड़ाने की तैयारी, ब्लॉक-पंचायत स्तर पर नेशनल कॉर्डिनेटर देंगे ट्रेनिंग

जयपुर(नि.सं.)। राजस्थान में स्थानीय निकाय व पंचायतराज चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की शुरुआत यूथ कांग्रेस ने राजस्थान से की है। यूथ कांग्रेस के राष्टीय महासचिव शेष नारायण ओझा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अभियान को लॉन्च किया।

39 साल से कम उम्र के यूथ जुड़ेंगे

यूथ कांग्रेस के राष्टीय महासचिव शेष नारायण ओझा ने बताया कि टास्क फोर्स जहां भी नगरीय निकाय चुनाव होंगे वहां पर यूथ को भाग लेने के लिए मोटिवेट करेगी। यह टास्क फोर्स ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करेगी, जो 39 साल से कम के हैं और संगठन से नहीं जुड़े, लेकिन संविधान को मानते हैं। ऐसे यूथ को ट्रेंड कर चुनाव लड़वाने में मदद की जाएगी।

ब्लॉक और पंचायत लेवल पर नेशनल कॉर्डिनेटर जायेंगे

वहीं, यूथ कांग्रेस के नेशनल कॉर्डिनेटर राजस्थान के सभी जिलों में ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जायेंगे। यूथ कांग्रेस का कहना है कि ऐसे युवा जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन संगठन तक जिनकी बात नहीं पहुंच पाती उनके लिए यह पंचायत टास्क फोर्स काम करेगी। टास्क फोर्स का मकसद ज्यादा से ज्यादा युवाओं को कांग्रेस से जोड़ना है।

कांग्रेस का फोकस 50 प्रतिशत युवा चुनाव लड़े - डोटासरा

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की इच्छा रही है कि युवाओं को जोड़ों। कांग्रेस का फोकस है कि 50 प्रतिशत युवा निकाय और पंचायत के चुनाव लड़े। डोटासरा ने कहा कि पंचायत फोर्स जिनको आइडेंटिफाई करेगी या सिलेक्ट करेगी उनको ही टिकट मिलेगी ऐसा नहीं है। फोर्स का काम रहेगा कि वे यूथ आई डेंटिफाई करना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। डोटासरा ने कहा कि टिकट कांग्रेस का जो प्रोसेस है उसी तरीके से मिलेगी। डोटासरा बोले- बीजेपी में फूट है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तावड़ा छाया को कोन पूछता है। कहा बीजेपी दिल्ली में फेल हो गई है। इनके यहां जो सबसे डमी कैंडिडेट होता है उसी की पर्ची निकलती है।

ईरान ने UAE के दावे को किया खारिज, मिसाइल दागने का लगाया था आरोप

तेहरान (एजेंसी)। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि ईरान ने उसके क्षेत्र की ओर मिसाइलें दागी थीं। यूएई ने मंगलवार को दावा किया था कि उसे ईरान से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता चला। इसके बाद ईरान की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने ने ईरान पर लगाए आरोपों पर खेद जताते हुए कहा, यूएई का यह कदम अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत के विपरीत है और क्षेत्रीय देशों के बीच विश्वास कायम करने तथा पश्चिम एशिया में असुरक्षा बढ़ने से रोकने के प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है।

तमिलनाडु में विधायकों को नई कार, रु.75 हजार भत्ता मिलेगा

महिला विधायक ने सदन में गाना गाकर धन्यवाद दिया

तमिलनाडु(एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को सभी विधायकों को सरकारी कार देने और वाहन के रखरखाव, ईंधन व ड्राइवर के खर्च के लिए हर महीने 75 हजार रुपए का भत्ता देने का ऐलान किया। इसके अलावा, विधायकों को असिस्टेंट रखने के लिए 25 हजार रुपए मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। विधानसभा में विधायकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। इसी दौरान TVK विधायक सिंधु ने तमिल सुपरस्टार और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (MGR) की फिल्म पड़गोट्टी का मशहूर गीत कोडुत्तदेलाम कोडुत्तान गाकर मुख्यमंत्री विजय का आभार जताया।

स्टेट जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाईः संदिग्ध और बोगस फर्मों के सर्वे में 1.38 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का खुलासा

जयपुर(नि.सं.)। स्टेट जीएसटी विभाग की टीम सोमवार को संदिग्ध और फर्जी लेनदेन करने वाली फर्मों के खिलाफ विशेष जांच अभियान (सर्वे) चलाकर बड़ी कार्रवाई कर 1.38 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं से खरीद और फर्जी बिलिंग/ई-वे बिल के जरिए भारी कर चोरी का मामला सामने आया है।

संदिग्ध आपूर्तिकर्ताओं से खरीद पर जीएसटी विभाग की कार्रवाई, 85 लाख की संभावित देयता

माधोराजपुरा, जयपुर में 17 अगस्त को राधे एंटरप्राइजेज के सर्वे में कार्रवाई के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से खरीद से संबंधित तथ्यों की जांच की गई। इस प्रकरण में लगभग 85 लाख रुपए की संभावित देयता सामने आई है। फर्म द्वारा कार्रवाई के दौरान 10 लाख रुपए स्वैच्छिक रूप से जमा कराए गए। विभागीय टीम ने पंचनामा तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों एवं लेखा पुस्तकों की जांच की।

सीकर में फर्जी कागजों पर चल रही बोगस फर्म का भंडाफोड़, 53.85 लाख रुपए की कर चोरी उजागर

सीकर की विशेष जांच (सर्वे) टीम ने पारीक ट्रेडर्स का सर्वे किया। इस कार्रवाई में फर्जी लेन-देन और 53.85 लाख रुपए की संभावित जीएसटी वंचना/कर चोरी का पर्दाफाश हुआ है। जांच में खुलासा हुआ कि करदाता द्वारा प्रारंभ से ही निरस्त आपूर्तिकर्ताओं से खरीद दिखाई गई तथा सप्लायर्स द्वारा जारी क्रेडिट नोट्स की इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया गया।

तीजोत्सव-2026

बीकानेर हाउस में चल रहा है दस दिवसीय 'तीजोत्सव-2026'

राजस्थानी परिधान भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्ध विविधता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक : कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में चल रहे 'तीजोत्सव-2026' का मंगलवार को अवलोकन करते हुए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थानी परिधान भारतीय संस्कृति और परंपरा की समृद्ध विविधता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों, लोक जीवन, रीति-रिवाजों और कला परंपराओं ने यहां की वेशभूषा को विशिष्ट पहचान प्रदान की है। पुरुषों की धोती-कुर्ता, अंगरखा, साफा और पगड़ी तथा महिलाओं की घाघरा-चोली, ओढ़नी और पारंपरिक आभूषण राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। प्रमुख आवासीय आयुक्त श्री रोहित कुमार ने केन्द्रीय मंत्री का तीजोत्सव 2026 में स्वागत करते हुए उन्हें उत्सव में लगे स्टॉल्स का अवलोकन करवाया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने स्टेज पर आकर सभी आंगतुकों को राजस्थानी कला और संस्कृति के बारे में अवगत करवाया। चौधरी तीजोत्सव के भव्य और सफल आयोजन के लिए प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी को तीज की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस अवसर पर प्रमुख आवासीय आयुक्त ने केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस उत्सव के आयोजन का उद्देश्य राजस्थान की लोक संस्कृति, कला, परंपरा एवं विरासत के संरक्षण और संवर्धन के साथ-साथ देशभर में राजस्थानी संस्कृति की विशिष्ट पहचान को और अधिक सुदृढ़ करना है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक संपादकः नीरज मेहरा द्वारा बोनस ग्राफिक्स, लक्ष्मी नगर, झोटवाड़ा मार्ग, अजमेर रोड़, जयपुर-302006 से मुद्रित एवं 141, दयानन्द नगर, फेज प्रथम झालाना डूंगरी गली नंबर 19, थाना गांधी नगर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। प्रबंध संपादक- पी.के.बृजवाल, 9950325930, 9571635930 (कानूनी सलाहकार एडवोकेट कैलाशनाथ भट्ट)